E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 4(1): 149-151
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 09-01-2022
Accepted: 12-02-2022

विशाखा सिंह नेहा
JRF, Political Science,
University of Rajasthan,
Jaipur, Rajasthan, India

Corresponding Author:
विशाखा सिंह नेहा
JRF, Political Science,
University of Rajasthan,
Jaipur, Rajasthan, India

नक्सलवाद : देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौति

विशाखा सिंह नेहा

सारांश
1967 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाडी में जमीदारों के खिलाफ अथियारबन्द आन्दोलन चलाया गया था। भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी से अलग हुये एक धडे ने नक्सल मूवमेंट के जनक माने जाने वाले चोरू मजूमदार के नेतृत्व में यह संघर्ष चलाया था। 1970 के दशक में किसानो की दशा कमजोर, दयनीय, बाल मजदूरी की अधिकता, बेरोजगारी में वृद्धि सामन्ती के अत्याचार की बढती प्रवृति भ्रष्टाचार एवं असमानता के ख्लिाफ इस आन्दोलन में लोग एकजुट हुये जो वर्तमान में साम्यवादी सरकारी की स्थापना तथा असमानता के खिलाफ संघर्ष के लये प्रयासरत है।
सर्वे के अनुसार भारत के 1 प्रतिशत लोगो के पास 73 प्रतिशत पैसा है जो की आय का अत्यधिक असमानता को प्रदर्शित करता है। सरकार के अनुसार अब नक्सलवाद देश के 11 राज्यो एवं 90 जिलो में फैला हुआ है। जो केवल 30 जिलो में अतिप्रभावी है। देश के जिन राज्यो में नक्सली हिंसा तीव्र उभार पर है छत्तीसगढ, बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश और उडीसा । आम धारणा यही है कि इन राज्यो में नक्सलवाद उभार की वजह इनका अविकसित होना है । वर्तमान समय में सिर्फ गरीबी व पिछडेपन को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है यह एक विचाराधारा है जिसे बाह्य समर्थन भी प्राप्त है। नक्सली आन्दोलन को राष्ट्र के लिये कभी भी चुनौती नही माना गया जबकि सर्वे के मुताबिक 2009 से 2021 तक नक्सली हमलो की संख्या तथा उनमें मारे गये नागरिको व सैनिको की संख्या जम्मू कश्मीर में हुये आंतकी हमलो की संख्या से अधिक है।
वष्र 2012 में डॉ0 मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद की देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बडा खतरा बताया तथा नक्सलवाद के खिलाफ 'जीरो टोलरेंस' की नीति अपनाने पर बल दिया। ऐसे में नक्सली आन्दोलन के खिलाफ लडाई आतंकवाद के खिलाफ अभियान से कही अधिक मुश्किल, दुरूह व चुनौतिपूर्ण है।

मूल शब्दः नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा, अथियारबन्द आन्दोलन

प्रस्तावना

नक्सलवाद क्या है।
चीन के साम्यवादी दल की विचाराधारा से प्रभावित भारत के साम्यवादी विचाराधारा पर अमल करने वाले लोगो ने पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाडी, हमारबाडी, तुमारबाडी आदि छोटे ग्रामीण स्थानो से नक्सलवाद की शुरूआत मानी जाती है।
1970 के दशक में अपनी जमीन पर नाजायज तरीके से आधिपत्य के कारण वहां के किसानो के भस्वामियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरूआत कर दी। इन किसानो को साम्यवादियो का प्रत्यक्ष समर्थन मिला। इस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित होकर एक हिंसक आन्दोलन का जन्म हुआ जिसे नक्सलवाद कहा जाता है।

नक्सलवादी विचाराधारा –
नक्सलवाद मार्क्सवादी और माओवादी विचाराधारा का पालन करता है, जो अपने अधिकारो की मांग को पूरी करवाने के लिये सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते है। शुरूआती समय में नक्सलवाद एक तरह का भूस्वामियो में अत्याचार के विरूद्ध आदिवासी किसानो द्वारा आरम्भ किया गया एक किसान आन्दोलन था जो अब पूर्ण सिस्टम का विरोधी बनकर हर मुमकिन अवसर पर हिंसा पर उतारू है।
गरीबी के खिलाफ होने वाली राज्य, वर्गो और जातियों की हिंसा तथा दमन, उत्पीडन से मुकाबला करने उसका सशस्त्र जवाब देने की इजाजत देती है। युवा नक्सलवादी आन्दोलन को सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी आन्दोलन के रूप में देखते है। नक्सलवाद के प्रति राज्य का रवैया मुख्य रूप से आग लगाने के कारणो को समाप्त करने के बजाय कही आग लग जाने पर उसे बुझाने के लिये दौडने का है। नक्सलवादी आज भी अपने अंतिम लक्ष्य क्रांति से हटे नही है लेकिन व्यवहार से उनकी मुख्य गतिविधियां अपने क्षेत्र की जनता के हितो के लिये लडना दूसरे गुटो को भी ऐसा करने में सक्षम बनाना और यह गारन्टी देना है कि हिंसात्मक स्थिति पैदा होने पर जब भी उनकी

जरूरत पडेगी वे उपलब्ध होगे । गरीब मेहनतकश जनता उन्हें अपना अंतिम व सबसे बडा रक्षक मानते है। नक्सवादी संसदीय रास्ते को गरीब जनता के लिये उपयोगी नही समझतें

अर्बन नक्सलवाद –

शहर में रहने वाले तमाम किस्म के लोग जो मौजूदा सत्ता का विरोध कर रहे है । इसमें मार्क्सवादी, समाजवादी, उदारवादी, मानवाध्किारवादी, पत्रकार, लेखक, वकील शामिल है। यह माओवादियों की एक तरह की रणनीति होती है जिसमें शहरो में नेतृत्व तलाशने, भीड जुटाने, संगठन बनाने और लोगो को इकट्ठा करके उन्हें तमाम चीजे, सामग्रीयो के साथ–साथ प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है । इस रणनीति के तहत शहरी क्षेत्रो में नेतृत्व तलाशने की कोशिश की जाती है। यह संगठन को मजबूत करने के साथ–साथ इसे बडा बनाने पर भी बल देते है। सभी सेक्यूलर ताकतो और धार्मिक अत्पसंख्यको को हिन्दू कासीवादी ताकतो के खिलाफ खडा किया जाये ।

नक्सलवाद के कारण –

आदिवासी इलाको में प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोगो का सरकार के प्रति असम्मानजनक दृष्टिकोण है सामाजिक बुराईया यथा गरीबी, कुपोषण बेरोजगारी अशिक्षा के कारण पिछले इलाको में नक्सलवाद को बढावा मिलता है वंचित वर्गो के लिये विशेष योजनाओं का अभाव यदि योजनाये है तो उनके समुचित क्रियान्वयन का अभाव होने के कारण असली हकदार लोगो तक इनका फायदा नही पहुंच पाया। नक्सलवाद की शुरूआत का मूल कारण स्थानीय जमीदारो के अत्याचार और भूमि अधिग्रहण के कारण उत्पन्न बेरोजगारी है। सरकार की रणनीतिक अस्पष्टता और नीतिगत विरोधाभास ने भी इसे बढावा दिया है।

नक्सलियो की क्षमताऍ यथा उनकी रणनीतिक सफलताएं तैयारी का दौर जिसमें वे अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते है एवं समर्थको की संख्या में वृद्धि करते है। इसके साथ ही उनके द्वारा सर्वहारा गणतंत्र की स्थापना जिसमें स्वतंत्र सरकार व जन अदालत शामिल है जिनका संसाधनो पर नियंत्रण है एवं जनजातियो को प्रभावित करती है। नीजिकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को बढावा दिये जाने के फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवसाि चरमरा गयी तथा विकास के नाम पर आदिवासियों एवं उनके संसाधनो का दोहन होने लगा । जिससे लाल गलियारा (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) में वृद्धि हुई जो पशुपति से तिरूपति अर्थात नेपाल से आंध्रप्रदेश तक फैला है।

अवस्थाऍ –

1967 में नक्सलवाद का उदय हुआ वंचितों के शोषण की रक्षा करने के लिये लेकिन 1970 में ही बांग्लादेश संकट के कारण आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिये सशस्त्र विद्रोह द्वारा इस आन्दोलन को कुचला गया। 1982 के दशक में इस आन्दोलन का पुर्नरूत्थान का दौर था और 1990 तक आते–आते यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये बडी चुनौति बन गया। 2004 तक का काल उतार–चढाव का काल रहा जो 2012 में चरमोत्कर्ष में बदल गया। 2012 के बाद सरकार द्वारा अपनाई गई 'जीरो टोलरेंस' की नीति के फलस्वरूप आन्दोलन पतन की ओर अग्रसर हो रहा है।

प्रभाव –

नक्सलवादियो का नारा 'सशक्त कृषि का रास्ता ही हमारा रास्ता है 'जनआधार का केंन्द्र बना। फलस्वरूप सर्वप्रथम केरल में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई जन आन्दोलन के फलस्वरूप जमीदारो से जमीन छीनकर वंचितों में वितरित की यह एक वैचारिक संधर्ष है जिसमें उग्रवाद, आतंकवाद एवं अलगाववाद तीनो का मिश्रण है जो कि वर्ग संधष्र की विचारधारा का समर्थन करते हुये सर्वहारा का बुर्जआ के खिलाफ विद्रोह है जिसे वामपंथी उग्रवाद का नाम दिया गया। यह सत्ता एवं व्यवसाि को खुली चुनौति प्रस्तुत करता है तथा साथ ही समानता, न्याय तथा संसाधनो के समान वितरण की पैरवी करता है। नक्सलवाद की उर्वर जमीन अनतर्राज्यीय सीमा, दुर्गम जंगल, पहाड, आदिवासी क्षेत्र आदि है।

नक्सवादी आन्दोलन के सकारात्मक प्रभाव भी प्रतीत हुये है जिसमें विचाराधारा की समझ, भूमिहीरनो व वंचितो तथा सर्वहारा के अधिकार, स्वतंत्रता समानता न्याय की स्थापना, समाजवादी सरकार की स्थापना, समाज में समतामूलक व्यवहार, भूमि सुधार, सामन्तवादी सोच में कमी, प्रशासनिक अत्याचार में कमी वंचितों का सशक्तिकरण, आदिवासियों का संगठन, राजनीतिक जवाबदेयता, प्रशासनिक सफलता प्राप्त हुये है।

नक्सलवादी आन्दोलन के नकारात्मक प्रभाव अधिक प्रतीत हुये है वंचितों के संरक्षक के तौर पर शुरू हुआ यह आन्दोलन संहारक के रूप में स्थापित हो चुका है जो कि स्वार्थी लडाई को महत्व देता है जो सरकार के विरूद्ध है। नक्सलवादियो द्वारा बाल नक्सल को बढावा दिया जाता है जिससे अशिक्षा में वृद्धि होती है। नक्सलवादियो द्वारा रक्षा प्राचीर के रूप में महिला व बच्चो को लाया जाता है जिससे उनके जान का भय रहता है। जन अदालत में दी जाने वाली यातनायें अमानवीय व हिंसक होती है। नक्सलियों में सत्ता व संसाधन का लालच बढने लगा है जिससे जनसमर्थन कम होने लगा है। सरकार द्वारा चलाये गये सल्वा जुडुम आन्दोलन में आदिवासियो ने ही नक्सलवादियो के खिलाफ बदूंक उठाई व उनका दमन किया।

नक्सली क्षेत्र में हमेशा जानमाल का संकट रहता है। नक्सलियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुचाने का भय सदैव बना रहता है। नक्सलियो द्वारा संविधान व संवैधानिक सरकार को चुनौति दी जाती रहती है प्रशासनिक शून्यता, चुनाव सम्पन्न व शांतिपूर्ण करवाने की चुनौति, जनजाति क्षेत्रो में विकास के लिए संसाधनो के दोहन की उनकी स्वीकृति के अनुसार करने की चुनौति रहती है।

नक्सलवाद आज भी जिंदा है क्योकि यह हमारे समाज के ऐसे खास क्षेत्रो की जरूरतों को पूरी करता है जिन्हें पूरा करने में दूसरा कोई भी दल सक्षम नही है। ये क्षेत्र है– दलितो और आदिवासियो के तथा ऐसे ही कुछ दूसरे गरीब तबको के। नक्सलवादियो के इन वग्रे की खासकर स्त्रियों की राज्य तथा स्थानीय प्रभावशाली वर्गो की हिंसा और उनके शोषण में हिफाजत की है। नक्सलवादियो ने इन शोषितो को संगठित किया है । उन्होने मजदूरी करने वाले दलित, आदिवासी स्त्री, पुरूषो की यूनियन बनाई और संघर्ष करके उनकी आर्थिक हालत को सुधारा जेसे भूमिहीनो की जमीन दिलाना भूमि सुधार किया, खदान मजदूरो की मजदूरी बढवाई।

सरकार के प्रयास –

नरम तत्व के बुद्धिजीवियों द्वारा नक्सलवाद के मुद्दे की सामाजिक और विकास संबंधी नीतियां का प्रश्न मानकर निपटाने की बात करते है । इन नरम तत्वों में सामाजिक कल्याण विभाग, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास और वन विभाग शामिल है। स्वैच्छिक संगठनो का भी उदय हुआ है जो सरकार को गरीबो के हित में नीतियां ओर कानून बनाने तथा कार्यक्रम लेने का सुझाव देते हे। ये स्वैच्छिक संगठन नक्सलवाद को सामाजिक समस्या के रूप में बताते है।

गरम तत्वो द्वारा कडे रूखो का समर्थन किया जाता है। इसमें वैधानिक, सुरक्षात्मक, राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रयास किये जा रहे है । वैधानिक प्रयासो में अनुसूची 5, 6 के तहत जनजाती एवं

अनुसूचित क्षेत्रो के लिये किये गये विशेष प्रावधान, स्वतंत्रता, समानता न्याय की स्थापना, मूल अधिकारो में वंचितो के अधिकार आदि संवैधानिक प्रयास किये गये है। कानूनी प्रयासो में आफस्था, निवारक निरोध कानून यथा टाडा, पोटा, रासुका के माध्यम से नक्सलवाद को कम करने के प्रयास किये गये है।

प्रशासनिक प्रयासो के अन्तर्गत नक्सलियो से बातचीत, समझौता, सीजफायर, आत्मसमर्पण (आवास, आजीवन रोजगार सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन) चुनाव (पंचायती राज में नक्सलियो को चुनाव में खडा है सत्ता का हस्तान्तरण करना) ई–गर्वनेंस की स्थापना (पारदर्शिता व जवाबदेयता में वृद्धि), सरकारी कार्यालयों की नक्सल प्रभावी क्षेत्रो में स्थापना जिससे जनता का भरोसा जीता जा सके । 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की भी मोदी जी द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ कार्यवाही कहा गया।

विकासात्मक प्रयासो के अन्तर्गत 30 नक्सल अतिप्रभावी जिलो में आधारभूत संरचना निर्माण के लिये विशेष राशि स्वीकृत की गई। सरकारी योजना 'न्यू इण्डिया' के अन्तर्गत पिछडे जिलो को विकसित किया जायेगा। पंचायती राज द्वारा स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करना। रोशनी योजना के तहत कौशल विकास पर बल देना, रोटी, कपडा, मकान के साथ सडक, बिजली उपलब्धता पर बल दिया जाये। मोबाइल सेवा को सुदृढ बनाना जिससे समायोजन एवं पहुंच सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षात्मक प्रयासो के अन्तर्गत सरकार द्वारा कठोर नियमों को अपनाया जाता है। जिसमें बोली नही गोली, स्पेशल बटालियन यथा कोबरा, विशेष दल, महिलाओं की बटालियन, सुरक्षा एजेन्सी की सतर्कता, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ग्रीन हंट प्रमुख है। इनमें सेनाओं को नये एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से लेंस हथियार दिये जाते हे। नक्सली क्षेत्र में आपदा प्रबंधन का कार्य भी किया जाता है जिससे उनके संसाधन संरक्षित रहे। सरकार द्वारा रणनीतिक प्रयासो के अन्तर्गत काउन्टर प्रोयोगेण्डा (विकास कार्य, स्कूल, बिजली), लोकल गुप्तचर एवं तीव्र विकास को महत्व दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सेनाओ की तैनाती पर विशेष बल दिया जाता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ समझौता कर इसरो के साथ भोगोलिक संवेदी प्रणाली तैयार की है। सेना द्वारा विशेष अभियान घेरो, रोको और हथियार न छोडे तो मारो चलाया गया है।

सरकार द्वारा 8 सूत्री कार्यक्रम स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटिजी, ट्रेनिंग सर्विलांस, बिजली टॉवर की उपलब्धता, मुख्य धारा में शामिल करना, स्कूल तक पहुच एवं वैक्सीन उपलब्ध करवाकर विश्वास प्राप्त किया जा सकता है।

नक्सलियो के प्रति आमजन का स्नेह तोडना भी आवश्यक है। संविधान की 5वीं अनुसूची के नियमों को सख्ती से लागू किया जाये जिससे आदिवासी अपने क्षेत्र का अपने हिसाब से नेतृत्व कर सके। सी.आर.पी.एफ. के लिये हेलीकोप्टर आवंटित किये जाये जिससे वे गतिविधियो पर नजर रख सके सर्विलांस ड्रोन के साथ–साथ हमलावर ड्रोन भी सेना को उपलब्ध करवाये जाये। बख्तरबंद गाडी, पर्याप्त संख्या में सैनिक, थर्मल इमेजिंग कैमरा, जासूरी उपकरण सेटेलाइट निगरानी आदि के माध्यम से इसे नियंत्रित एवं समाप्त किया जा सकता है। यह एक कम्यूनिष्ट की विचारधारा है जो वर्तमान में 30 जिलो में माओवादी का राज है जहां उनका अपना कर, भारत सरकार का संविधान नही, उनकी सेना, उनका संविधान चलता है।

सुझाव –

संविधान संशोधन कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रो को केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत ले लिया जाना चाहिये जिससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रो में उच्च श्रेणी की आधारभूत संरचनात्मक सुविधायें तैयार की जाये। भूमि सुधार नक्सलवाद का प्रमुख कारण है इसलिये फारेस्ट एक्ट लागू किया जाना चाहिये। प्राकृतिक संसाधनो पर स्थानीय आदिवासियो को समान अधिकार दिये जाये तथा इन अधिकारो का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाये। मादक पदार्थो तथा हथियारो की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जाये तथा सरकारी नौकरियो में स्थानीय लोगो को वरीयता दी जाये। सामाजिक व्यवस्था में सामन्तवादी मानसिकता व आर्थिक साधनो पर वर्ग विशेष का आधिपत्य समाप्त किया जाये। जनजातीय क्षेत्रो में स्थानीय लोगो की सहमति से सेज व पावर प्लांट लगाए व सडको का विकास किया जाये तथा उन्हं जिला के ही से जोडा जाये। नक्सल प्रभावी क्षेत्रो में लागू की जाने वाली विकास योजनाओ में नक्सलवादियो की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

वर्तमान स्थिति –

अपने हक की लडाई के लिये शुरू हुआ यह संगठन आज अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ सिद्धि के लिये कार्यरत है। वर्तमान समय में नक्सलवादियो के पास लगभग वह सभी आधुनिक तकनीकी उपलब्ध है जो सीमापार आतंकवादियो और नेपाल के माओवादियो के साथ है।

भारत के कई हिस्सो में नक्सलवादी आन्दोलन आज भी कारगर है क्योकि समाज में कुछ ऐसे तीखे अंतर विरोध मौजूद है जिन्हें सुलझाने के गंभीर प्रयास नही किये जा रहे। दलित आदिवासियों और दूसरे गरीब तबको के अंदर भारतीय संविधान ने अपनी प्रगति की जो आशाएं जगाई थी उन्हें आज तक किसी भी शासन ने पूरा नही किया । सिर्फ जन संघर्षो के जरिए ही इन अंतरविरोधो को हल किया जा सकता है । इन आशाओ को पूरा किया जा सकता है।

एक ऐसी समन्वित नीति अपनायी जाये जिससे नक्सली लोगो को समाज की मुख्य धारा में समाहित किया जा सके क्योकि टुकडो में किया जाने वाला कोई भी प्रयास सिीति को दुरूहता ही प्रदान करेगा। कोई स्थायी समाधान नही दे पायेगा। इससे यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि नक्सलवाद एक भयंकर राष्ट्रीय सुरक्षा व विकास के समक्ष चुनौति के रूप में सभी के सामने है। इसके फैलाव को रोकने के लिये सरकार ने उचित तैयारी भी की है लेकिन जरूरत है इनको प्रभावी ढंग से लागू करने की तभी नक्सलवाद समाप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. डॉ0 जयवीर सिंह : नक्सलवाद का भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव, 2015 पृ.सं. 118–126
2. वीर भारत तलवार : नक्सलबाउी के दोरे में , 2007 पृ.सं. 641
3. B.K. Menon: who are the naxels? A threat to Indian democracy, 2011 पृ.सं. 2014
4. डॉ0 लक्ष्मी शंकर यादव : नक्सलवाद का बढता खतरा, 2010 पृ.सं.65
5. डॉ0 लक्ष्मी शंकर यादव : नक्सलवाद का बढता खतरा, 2010 पृ.सं.65
6. सिविल सर्विसेज टाईम्स, 2009 पृ.सं. 6–7
7. ए.एस. नारंग : भारतीय शासन व राजनीति पृ.सं. 265
8. पदमसिंह गजराज चेतना गजराज, भारतीय राजनीति राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे और चुनौतियां, 2014 पृ.सं. 209–2016
9. A. Alowageer, sumant swain, manish patel : Naxal Movement an Idcological conflict पृ.सं. 230
10. विवेक एस. राज : नक्सलवाद लालगढ के आइने में : सिविल सर्विसेज टाइम्स 2009 पृ.सं. 6